उत्तर प्रदेश विस चुनाव : पार्टियों के पास मुद्दा ही नहीं

भाजपा ने फ़िर अलापा राममंदिर का राग

चुनाव 'लोकतंत्र' का महापर्व होता है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण 'लोकतंत्र' का महापर्व पूरे जोर-शोर से मनाया जा रहा है। सभी दलों के नेता और प्रत्याशी तरह-तरह से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। दारू बंटनी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनावों के मुख्य युद्ध स्थल उत्तर प्रदेश से ख़बर आई है कि अपने आप को भारतीय संस्कृति (हिंदू संस्कृति) का मुख्य पैरोकार मानने वाली भाजपा के नेता संभावित मतदाताओं को नियमित रूप से दारू बांट रहे हैं, इतनी ज़्यादा कि मुफ़्त की दारू बेहिसाब पीकर एक नवजवान मर भी गया। बहरहाल, दारू के मुफ़्त वितरण के बिना 'लोकतंत्र' का यह महापर्व पूरा नहीं होता। दारू के साथ मतदाताओं का मनोरंजन करने के लिए नाचने-गाने वाली लड़कियां भी चाहिए। मतदाताओं में मुंबई की बार गर्ल्स का ज़्यादा ही क्रेज़ है। पार्टियां अब नाचने-गाने वाली लड़कियों को भाड़े पर लाने के इंतज़ाम में लगी हुई हैं। बहुत सी पार्टियां तो ऐसी हैं जो बॉलीवुडी हीरोइनों का परेड करा देती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा होगा। भरपूर फ़ीस मिले तो बॉलीवुड की कई नामचीन हीरोइनें कम से कम कपड़ों में मतदाताओं को अपने लटके-झटके दिखाने को तैयार रहती हैं।

बहरहाल, इन चुनावों में राजनीतिक दलों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। न दिन-ब-दिन सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही ग़रीबी का मुद्दा, न शिक्षा का मुद्दा, न स्वास्थ्य का मुद्दा, न बेरोजगारी का मुद्दा। मुद्दों का पूरी तरह से अभाव है। एक भ्रष्टाचार का मुद्दा सभी मुद्दों पर छा गया था और टीम अन्ना ने चुनावों के दौरान इसे उठाने का शोर-शराबा मचाया था। पर अब टीम अन्ना कहां है और क्या कर रही है, इसका किसी को कोई पता नहीं।

राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, पंजाब विधानसभा चुनाव और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव महत्त्वपूर्ण हैं। पर इनमें में भी सबसे ज़्यादा महत्त्व उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सांसद इसी प्रदेश से चुन कर आते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम केंद्र की राजनीति को प्रभावित करेंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बसपा, भाजपा, सपा और कांग्रेस मुख्य मुकाबले में हैं। और भी कई दल चुनाव मैदान में हैं, पर उनका विशेष महत्त्व नहीं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रखा है। राहुल गांधी मतदाताओं से तरह-तरह के दावे कर रहे हैं, पर केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही संप्रग सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ रखे हैं। विदेश मंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री दोनों घोटालों के मामले में फंसे हैं। विदेश मंत्री के खिलाफ कर्नाटक के लोकायुक्त ने तो मुकदमा चलाने का आदेश जारी कर रखा है, पर किसी प्रकार से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पर अस्थायी रोक लगवायी है। पर आज नहीं तो कल कर्नाटक में अवैध खनन के मामले में इन पर मुकदमा चलना तय है। पर कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए उन्हें आरक्षण का झुनझुना थमाने की कोशिश की है जिसका विरोध भाजपा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करने का प्रयास कह कर कर रही है। मायावती ने तो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त कर और पार्टी से निकाल कर अपने आपको पाक-साफ़ साबित करने का प्रयास किया है, पर वे कितनी पाक-साफ़ हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। पर उनके पास दलित वोट बैंक तो है ही, अगड़ी जातियों को भी पूर्व की भांति उन्होंने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। यह कोशिश कहां तक कामयाब होती है, इसका पता चुनाव परिणाम सामने आने पर लगेगा, पर चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि राजनीति की शातिर खिलाड़ी मायावती अपनी तिकड़मबाज़ियों के बल पर फ़िर से सत्ता पाने में सफल रहेंगी।

जहां तक मुलायम का सवाल है, इस बार इन्होंने कमान अपने पुत्र अखिलेश यादव को सौंप दी है। मुलायम को पिछड़ी जातियों और मुसलमानों के वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। मुद्दे की कोई बात तो इन्होंने भी नहीं की है, हां यह कर बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रत्येक बेरोजगार को दो हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर होगी, इसके बारे में इन्होंने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा, पर भत्ता देने का प्रलोभन दे दिया। राज्य में बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सारा खज़ाना भत्ता देने में ही साफ हो जायेगा। स्पष्ट है कि इस तरह के झूठे प्रलोभन देकर सपा सत्ता में आने के ख्वाब को हकीकत में नहीं बदल सकती।

जहां तक भाजपा का सवाल है, उसके सामने सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यही बन गया है कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा - राजनाथ सिंह या साध्वी उमा भारती? अभी इसी सवाल पर इन दोंनों के गुटों में सिर-फुड़ौव्वल की स्थिति नज़र आ रही है। भाजपा अध्यक्ष गडकरी ज़मीनी सच्चाइयों से नावाकिफ़ हैं। भाजपा ने अपने पांवों में कुल्हाड़ी तभी मार ली थी जब उसने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले के सूत्रधार बसपा के बर्खास्त परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को अपने साथ पिछड़ी जातियों के वोट पाने की लालच में जोड़ा था। इससे भाजपा में घोर अंतर्कलह की स्थिति पैदा हो गई थी। अंततः भाजपा नेतृत्व के इशारे पर कुशवाहा ने स्वयं को भाजपा से अलग कर लिया, पर इससे भाजपा का जो नुकसान होना था, वह हो चुका। भाजपा के इस कदम से आडवाणी के भ्रष्टाचार विरोधी जनचेतना रथयात्रा की हवा भी निकल गई। अब पार्टी में यह स्थिति है कि आडवाणी की कोई सुनने वाला भी नहीं। सुषमा स्वराज, जेटली आदि ही मुख्य भूमिका में हैं। राज्य स्तर पर भाजपा नेताओं के अपने-अपने गुट हैं जो वर्चस्व स्थापित करने के संघर्ष में लगे रहते हैं। भाजपा ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी कोई दम नहीं है। हां, उसने एक बार फ़िर राममंदिर निर्माण के सवाल को खड़ा कर दिया है। यह मुद्दा मर चुका था, पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ने फ़िर से इस मरे मुद्दे को जिलाने की कोशिश की है जिससे उसे नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। राममंदिर मुद्दा खड़ा करने से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को कोई लाभ तो मिलने से रहा, 2014 में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर वह अपने टूटे-फूटे गठबंधन को फ़िर से संगठित और मजबूत करना चाहती थी, वह भी नहीं हो पायेगा।

पहले ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा दूसरे या तीसरे नंबर पर आ सकती है, पर इसके आत्मघाती कदमों को देखते हुए लगता है कि यह कहीं चौथे नंबर पर न आ जाये। भाजपा ने जो आत्मघाती कदम उठाये हैं, इसका फ़ायदा निस्संदेह कांग्रेस और सपा को मिलेगा। बहरहाल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी जीते, आम जनता पर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लोकतंत्र के लूटतंत्र में बदल जाने के कारण जनता के सामने लुटने और शोषण-उत्पीड़न का शिकार होने के सिवा और कोई चारा नहीं है। पूरी तरह से विकल्पहीनता की स्थिति है। उम्मीद की कोई किरण कहीं नज़र नहीं आती। इसलिए यह बेहिचक कहा जा सकता है कि अभी राजनीतिक-सामाजिक अराजकता का दौर जारी रहेगा। इस दौर में आम जनता की मुसीबतें बढ़ने ही वाली हैं। जनपक्षधर ताकतें निराशा-हताशा की दशा में हैं और आम जनता की राजनीति करने का दावा करने वाले संगठनों में विखंडन की अंतहीन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बड़ी मौजू लगती है -

– शिवशंकर

सलमान रश्दी भारत नहीं आये

अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के लिए सभी दलों ने लगाया पूरा जोर

आख़िरकार अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की सांप्रदायिक राजनीति करने वाले दलों ने जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में भाग लेने के लिए आ रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित व विवादास्पद लेखक सलमान रश्दी के मामले को 'मैनेज' कर ही लिया। सलमान रश्दी भारत नहीं आये। इससे कांग्रेस समेत तथाकथित तमाम सेकुलर दलों ने राहत की सांस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है, पर वह हिंदू सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए बदनाम है। यह एक अजीब विडंबना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर काबिज़ होने के लिए सभी दलों ने कठमुल्लों की गैर जनतांत्रिक मांग के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, बल्कि इस मुद्दे को पर्दे के पीछे से हवा दी जबकि 'सैटेनिक वर्सेज' संबंधी विवाद के ठंडा पड़ जाने के बाद रश्दी कई बार भारत आ चुके हैं। उन मौकों पर भी कठमुल्लों को चाहिए था कि वे रश्दी के भारत आगमन का विरोध करते। पर पहले तो उन्होंने ऐसा किया नहीं। इससे साबित होता है कि मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने के लिए अपने राजनीतिक आकाओं की शह पर कठमुल्लों ने इस बार रश्दी के भारत आगमन का विरोध किया। पर इससे पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की छवि खराब हुई है। लेकिन अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दलों को इससे क्या मतलब! उन्हें तो येन-केन-प्रकारेण थोक में मुसलमानों का वोट चाहिए और इसके लिए इस मुद्दे से बढ़िया और कोई मुद्दा उन्हें मिल नहीं सकता था। लेकिन इससे मुसलमानों के पिछड़ेपन को ले कर 'टसुए' बहाने वाले तमाम राजनीतिक दलों की यह असलियत सामने आ गई है कि वे उनके कितने हितैषी हैं। सलमान रश्दी के भारत आने से मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। कठमुल्लों को प्रसन्न करने के लिए जब भारत सरकार ने उनके उपन्यास 'सैटेनिक वर्सेज' को प्रतिबंधित किया तो इससे भी आम मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी हालत जस की तस रही।

दरअसल, इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को मुसलमानों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने से कोई मतलब नहीं है, मतलब है उन्हें उनके वोटों से ताकि वे सत्ता हासिल कर सकें। मुसलमानों के जो कठमुल्ला नेता हैं, उन्हें भी आम ग़रीब मुसलमानों की दशा में सुधार से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी दशा तो बहुत ही सुधरी हुई है। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। उसी दौलत के बल पर लंबी-लंबी दाढ़ियां बढ़ाये कठमुल्ले इस धरती पर ही जन्नत के सारे मजे लूटते हैं और ग़रीब मुसलमानों को धर्म की अफ़ीम पिला कर हर तरह की जलालत में डाले रखते हैं। वे अपने आप को उनका 'मसीहा' मानते हैं, पर वास्तव में वे उनके वोटों के ठेकेदार की भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि हर चुनाव के वक्त तमाम राजनीतिक दलों के नेता इन बेगैरत कठमुल्लों के पांवों की धूल अपने माथे पर लगा कर मुस्लिम वोटों का इंतज़ाम पक्का कर लेना चाहते हैं। अब ये कठमुल्ले जिस पार्टी के पक्ष में वोट देने का फ़तवा जारी करते हैं, हर तरह से पिछड़ी, अनपढ़ और जलालत की ज़िंदगी जीने वाले मुसलमान भेड़ों की तरह कतार में लग कर वोट दे देते हैं। इसके बाद फ़िर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। भारी से भारी संकट में घिरने पर वे 'खुदा' से रहम की दुआ मांगते हैं, पर कभी खुदा उनकी मुसीबतों को दूर करने नहीं आता और अपने आप को खुदा के बंदे कहने वाले कठमुल्ले ही उनकी सहायता करने नही आते हैं।

इस बार अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में माहिर कांग्रेस ने पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत कोटे में पिछड़े मुसलमानों के लिए छः प्रतिशत कोटा तय किया। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने तो मुसलमानों को प्रलोभित करने के लिए कह दिया कि इन्हें नौ प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। पर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण वास्तव में यह सब हो नहीं पाया। सवाल यह है कि मुसलमान आरक्षण से लाभ तभी उठा सकते हैं जब वे पढ़े-लिखे हों, अन्यथा उन्हें 50 प्रतिशत आरक्षण भी दे दें तो उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिलेगा।

संप्रग सरकार द्वारा गठित सच्चर आयोग मुसलमानों के पिछड़ेपन से संबंधित अपनी रिपोर्ट कई वर्ष पहले ही सरकार को सौंप चुका है, पर उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हां, सच्चर आयोग की रिपोर्ट की चर्चा खूब हुई।

खास बात यह है कि किसी भी समुदाय का विकास अलग से किया भी नहीं जा सकता। जहां तक पिछड़ेपन का सवाल है, सिर्फ़ मुसलमान ही पिछड़े नहीं हैं। ऐसी अनेकों जातियां और समुदाय हैं जिनकी हालत मुसलमानों से बेहतर नहीं है। अगर सरकार विकास के कार्यक्रम चलायेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत जरूरतों को पूरा करेगी, रोज़गारों का सृजन करेगी तो उससे मुसलमानों के साथ ही साथ सभी पिछड़ी जातियों और समुदायों को लाभ होगा। सबका विकास होगा। पर सरकार का लक्ष्य मुसलमानों और अन्य पिछड़े तबकों का विकास करना नहीं है, उसका एकमात्र लक्ष्य चुनाव में वोट पाने के लिए तरह-तरह की तिकड़म करना है और इसमें सत्ताधारी दलों के साथ कोई भी दल पीछे नहीं है। अगर विकास के मुद्दे पर मुसलमानों को गोलबंद किया जाता तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने कठमुल्लों के सहारे एक ऐसे मुद्दे पर मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने की कोशिश की जिससे आम मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं है। आख़िर कितने मुसलमान सलमान रश्दी का नाम जानते हैं और कितने कठमुल्लों ने उनकी वह किताब पढ़ रखी है जिसकी वजह से उन्होंने रश्दी के भारत आगमन का विरोध किया। इस तरह की बातें मुस्लिम समुदाय को और पीछे ही ले जायेंगी।

आम ग़रीब मुसलमानों को चाहिए कि वे कठमुल्लों के चक्कर में न फंसे। ये धर्म के नाम पर सिर्फ़ उन्हें उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। सलमान रश्दी के भारत आने से इसलाम को कोई ख़तरा नहीं पहुंचता और न ही आम मुसलमानों का ही कोई अहित होता।

आज अपने आप को सेकुलर कहने वाली सभी पार्टियां अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मौका देख कर कभी अल्पसंख्यक तो कभी बहुसंख्यक सांप्रदायिक राजनीति करती रही है। अल्पसंख्यक सांप्रदायिक राजनीति की आधारशिला औपनिवेशिक शासकों ने बड़े ही साज़िशाना तरीके से इस देश में रखी थी जिसके परिणामस्वरूप देश का विभाजन हुआ जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है।

प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर हरबंस मुखिया का कहना है कि सांप्रदायिकता सिर्फ़ हिंदू ही नहीं होती, यह मुस्लिम भी होती है। अतः दोनों तरह की सांप्रदायिकता के ख़तरे की पहचान करना जरूरी है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद्, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठन हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं तो कठमुल्लों के भी अनेकानेक संगठन मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ़ राजनीतिक सत्ता हासिल करना होता है।

इसलिए अगर पिछड़े मुसलमान जलालत की ज़िंदगी से मुक्ति चाहते हैं और वास्तव में अपना विकास करना चाहते हैं तो उन्हें कठमुल्लों और नकली 'मसीहाओं' से दूर रहना होगा आगे बढ़ने के लिए संघर्ष की राह को अपनाना होगा।

– ए. अहमद